(ख) मंत्रालय, इसके विभागों, संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

उद्योग मंत्रालय में औद्योगिक विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम): (क) चालू वर्ष में इस मंत्रालय की हिन्दी सलाहकार समिति की अब तक दो बैठकें आयोजित की गई हैं । हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी स्थानीय सदस्यों को औद्योगिक विकास विभाग तथा इसके कुछ संबद्ध और अन्य कार्यालयों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों पर भी पर्यवेक्षकों के रूप में नामित किया गया है ।

(ख) हिन्दी अनुभाग के अतिरिक्त औद्योगिक विकास विभाग का सामान्य प्रशासन अनुभाग शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में कर रहा है ।

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का अनुपालन किया जा रहा है ।

राजभाषा अधिनियम का लागू किया जाना

152. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या **ऊर्जा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उनके मंत्रालय से संबद्ध हिन्दी सलाहकार समिति की इस वर्ष कितनी बैठकें हुई और राजभाषा कार्यान्वयन समिति में सभी स्तरों पर गैर-सरकारी सदस्यों को पर्यवेक्षक के रूप में नामित किए जाने के संबंध में क्या स्थिति है ;

(ख) मंत्रालय, इसके विभागों के संस्थानों और अधीनस्थ कार्यालयों में, हिन्दी अनुभाग को छोड़कर किस-किस अनुभाग में शत-प्रतिशत कार्य हिन्दी में किया जा रहा है तथा यह किस-किस तारीख से किया जा रहा है तथा किन मामलों में हिन्दी को अब तक नहीं अपनाया गया है तथा इसके क्या कारण हैं ; और

(ग) राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) को मंत्रालय स्तर से निम्नतम स्तर तक पालन न किए जाने के क्या कारण हैं जबकि अधिनियम को पारित हुए 24 वर्ष तथा वार्षिक कार्यक्रम को तैयार किए 10 वर्ष हो चुके हैं ?

ऊर्जा मंत्री (श्री वसंत साठे) : (क) ऊर्जा मंत्रालय के तीनों विभागों अर्थात कोयला विभाग, विद्युत विभाग तथा अ-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग, में हिन्दी सलाहकार समितियों की चालू कलेंडर वर्ष में अब तक चार बैठकें हो चुकी हैं । अ-पारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग तथा कोयला विभाग की समितियों की अगली बैठकें क्रमशः 25 नवम्बर, 1987 तथा 3 दिसम्बर, 1987 को आयोजित की जा रही हैं । इन समितियों के गैर-सरकारी सदस्यों का मार्गदर्शन और सलाह प्राप्त करने के लिए कोयला विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के गैर-सरकारी सदस्यों को विभिन्न कोयला संगठनों की राजभाषा कार्यान्वयन समितियों में तथा अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत विभाग की हिन्दी सलाहकार समिति के एक सदस्य को विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति में नामित किया गया है ।

(ख) कोयला विभाग के प्रशासन-II अनुभाग, आई० आर० अनुभाग, सी० एस० डब्ल्यू , अनुभाग तथा सी० पी० अनुभाग में तथा अन्य दोनों विभागों के प्रशासन स्कंधों में काफी हद तक सरकारी कामकाज में हिन्दी का प्रयोग हो रहा है। शेष अनुभागों में कामकाज में हिन्दी का प्रयोग बढ़ाने के लिए प्रयास किया जा रहा है ।

(ग) ऊर्जा मंत्रालय में राजभाषा अधिनियम की धारा 3(3) का शत-प्रतिशत पालन करने के लिए पूरी निष्ठा से प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्रालय के तीनों विभागों के मुख्यालयों में धारा 3 (3) का लगभग पूरी तरह पालन किया जाता है। अधीनस्थ संगठनों में भी इस धारा का पूरा पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रयत्न जारी है।

प्राकृतिक गैस की संभावनाएं

153. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश में प्राकृतिक गैस की क्या संभावनायें हैं तथा इस संबंध में किए गए विभिन्न सर्वेक्षणों का ब्यौरा क्या है तथा प्राकृतिक गैस प्राप्त करने में किस सीमा तक सफलता प्राप्त हुई है ?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त) : 1-1-87 को भंडारों के आधार पर 1987-88, 1988-89 और 1989-90 वर्षों के लिए टर्मिनल गैस उत्पादन क्रमश: 27.34, 33.36 और 39.78 मिलियन घन मीटर प्रतिदिन होगा।

देश के विभिन्न भागों में हाइड्रोकार्बन के अन्वेषण के लिए किए गए भूवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण-चुम्बकीय और भूकम्पीय सर्वेक्षणों से 1-1-1987 को 606460 मिलियन घन मीटर मुक्त गैस तथा 39854 मिलियन घन मीटर सम्बद्ध गैस के भण्डारों का पता लगा है।

देश में पनबिजली परियोजनाएं

154. **श्री जगदम्बी प्रसाद यादव** : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पनबिजली की क्या संभावना है, इस संबंध में कहां-कहां सर्वेक्षण कराया गया है और कहां-कहां सर्वेक्षण किया जा रहा है और निकट भविष्य में इसके लिए क्या योजना है ; और

(ख) पहाड़ी राज्यों में कहां-कहां ऐसी परियोजनायें बनी हैं, इनमें से प्रत्येक परियोजना का अनुमानित मूल्य कितना है और उत्पादन क्षमता कितनी है और इन परियोजनाओं पर काम कब तक आरंभ हो जाने की संभावना है ?

ऊर्जा मंत्रालय में विद्युत विभाग में राज्य मंत्री (श्रीमती सुशीला रोहतगी) : (क) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा देश में जल विद्युत शक्यता संबंधी किए गए पुनर्मूल्यांकन के अनुसार 60% भार गुणांक पर 84044 मैगावाट जल विद्युत शक्यता का अनुमान लगाया गया है। विभिन्न राज्यों में बृहत्त नदी के बेसिन में अनुमानित जल विद्युत शक्यता को दर्शाने वाला विवरण-I संलग्न है। (नीचे देखिये)।

(ख) पर्वतीय राज्यों में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजनाओं तथा निर्माण की जाने वाली परियोजनाओं के आयोजना, इनकी अनुमानित लागत, प्रतिस्थापित क्षमता तथा चालू करने की तारीख के साथ इनकी सूची विवरण-II में दर्शाई गई है।

विवरण-I

भारत की जल विद्युत सक्षमता

राज्य	60% भार आनुपात पर क्षमता (मेगावाट)
1	2
जम्मू और कश्मीर . .	7487
हिमाचल प्रदेश	11647
पंजाब . . .	922
हरियाणा . . .	64
उत्तर प्रदेश . . .	9744
राजस्थान . . .	291
जोड़ उत्तरी क्षेत्र :	30155